प्रदेश में निवेश की राह और आसान बनाने की तैयारी

यूपी निवेश मित्र सिंगल विंडो सिस्टम विधेयक लाएगी सरकार

Premshanker.Mishra
@timesofindia.com

■ **लखनऊ :** ईज ऑफ डूइंग विजनेस में अचीवर स्टेट का तमगा हासिल कर चुके यूपी में निवेश की राह में तकनीकी अड़चनों और लालफीताशाही की बची दीवारों को तोड़ने के लिए सरकार 'यूपी निवेश मित्र सिंगल विंडो सिस्टम ऐक्ट' लाएगी। इसके जरिए कई अनुमतियों की समयबद्धता को कानूनी जामा पहनाया जाएगा। साथ ही अलग-अलग कानूनों में छोटे-छोटे मामलों को लेकर किए गए दंडात्मक प्रावधान भी खत्म किए जाएंगे। बजट सत्र में यह कानून पास कराने की तैयारी है।

अनुमति की प्रक्रिया सहज होगी, कई कानूनी अड़चनें भी हटेंगी

प्रदेश में उद्योग लगाने व निवेश करने के लिए आवेदन व अनुमति की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। निवेश मित्र पोर्टल के जरिए सरकार उद्योगों को यह सहूलियत दे रही है। इकाईयों के लिए विभिन्न तरह की एनओसी, लाइसेंस के साथ ही अलग-अलग औद्योगिक नीतियों के तहत इंसेंटिव की प्रक्रिया भी इस पोर्टल के जरिए आगे बढ़ाई जाती है। इसे और सहज और समयबद्ध करने के लिए इंडस्ट्री विभाग एक्ट का प्रस्ताव तैयार कर रहा है।

AI Image

10 लाख से अधिक उपयोगकर्ता हैं निवेश मित्र पोर्टल पर

490 से अधिक सेवाओं के लिए ऑनलाइन अनुमति

16 लाख से अधिक आवेदन आए हैं 6 सालों में

42 विभागों की एनओसी व लाइसेंस से जुड़ी सेवाएं पोर्टल पर

ताकि न रहे हिचक

अब भी कई ऐसे कानून हैं जिनको लेकर निवेशकों में हिचकिचाहट की स्थित है। म्युनिसिपेलिटी एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट के तहत छोटे-छोटे मसलों में जेल व जुर्माने के प्रावधान हैं। ऐसे नियम-कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव है। अब उद्योगों या उससे जुड़े जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने के लिए जेल के बजाय जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए अपील की भी अलग-अलग मैकेनिज्म बनाने का प्रस्ताव है। सेवाओं की अनुमति की टाइमलाइन को और व्यावहारिक बनाया जाएगा। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भी आवेदन अटके होने पर डीम्ड अप्रूवल जैसे प्रावधान का भी प्रस्ताव है।

इसलिए भी कवायद

योगी सरकार ने यूपी को 1 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने का लक्ष्य रखा है। उद्योग व निवेश की इसमें अहम भूमिका है। लगभग दो साल पहले हुए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इसमें 10 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो चुकी है। सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक निवेश प्रस्तावों की जमीन पर उतारा जाए। इसलिए, निवेशकों की सहूलियत को बढ़ाने और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं।